जिला प्रशासन खण्डवा अंतर्गत इ-गवर्नेंस के रूप में निम्नांकित प्रोजेक्ट चल रहे है

1. एगमार्क नेट Agmarknet : (http://agmarknet.nic.in) कृषि उत्पाद विपणन संबंधी यह प्रोजेक्ट सन् 2002 में लांच किया गया । इसमें जिंसवार दैनिक आवक,गुणवत्ता,न्यूनतम अधिकतम और औसत भाव को इन्टरनेट पर कृषक और व्यापारियों के हितार्थ रखा जाता है । दैनिक रिकार्ड को उसी दिन संध्या में अपलोड कर दिया जाता है, इस प्रकार कृषक और व्यापारीबंधु पूरे भारतवर्ष की कृषि उपज मण्डियो के भावो को देख सकते हैं । इसके अतिरिक्त मण्डी संबंधी अन्य जानकारियों का भी इसमें समावेश है । प्रारंभ में 2 कृषि उपज मण्डियो, खण्डवा और बुरहानपुर को इसके अंतर्गत लिया गया था । इसके उपर वर्कशाप्स और प्रशिक्षण कार्यक्रम के अतिरिक्त जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए गए हैं ।

2. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग स्टूडियो :- जिले मे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग स्टूडियो नबम्वर 2004 से एन. आई. सी द्वारा संचालित हो रहा है जो पहले VSAT द्वारा काम करता था, अब यह 34 mbps की लीज-लाईन पर संचालित होता है। इस सुविधा का उपयोग कई विभागों द्वारा जिला स्तर के अधिकारियों से बातचीत के लिये किया जा रहा है। हर माह 30-40 वीडियो कॉन्फ्रेंस संचालित होती है।

3. स्थानीय कंप्यूटर नेटवर्क :- एन. आई. सी द्वारा जिलाध्यक्ष एवं अन्य कार्यालयों में स्थानीय कम्प्यूटर नेटवर्क का संचालन किया जाता है। इस नेटवर्क मे 50-60 कम्प्यूटर एन. आई. सी के नेटवर्क मे कार्य कर रहे है। नेटवर्क के कम्प्यूटर पर एन. आई. सी द्वारा एंटी वायरस स्थापित किया जाता है ताकि नेटवर्क वाईरस रहित रहे.।

4. पिछडा क्षेत्र अनुदान निधि Backward Region Grant Fund : (http://brgf.gov.in) सन् 2006 में यह लांच किया गया । स्थानीय निकायों और ग्रामीण निकायों की मेपिंग खण्डवा और बुरहानपुर दोनेा जिलो के लिए की गई है । इसके उपरांत विधानसभा क्षेत्रों और संसदीय क्षेत्रों की इन निकायों पर मेंपिंग का कार्य किया गया ।

5. Planplus (http://planningonline.gov.in) विकेंद्रीकृत योजनांतर्गत इसे 2009 में लांच किया गया । इसमें प्लानिंग प्रोसेस के वर्कफ्लो को केप्चर किया जाता है । फलानिंग से आगे जाकर मॉनिटरिंग और कण्ट्रोल प्रोसेस को भी इसमें लिया गया है । निचले (ग्राम या वार्ड स्तर पर अपनी आवश्यकताओं के आधार पर योजना बनाई जाती है और क्रमशः उच्च स्तर की योजनाओं को इन्ही निचले स्तर की योजनाओं को शामिल करते हुए बनाया जाता है इस प्रकार सिद्धान्ततः राज्य और राष्ट्रीय स्तर की योजना बनाना इस प्रोजेक्ट का महत्वाकांक्षी लक्ष्य है ।

6. जिले की वेबसाईट District Website (http://www.khandwa.nic.in) जिला खण्डवा स्थित राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र व्दारा खण्डवा जिले की वेबसाइट http://www.khandwa.nic.in का निर्माण कर रखरखाव सन् 2000 से किया जा रहा है । इसमें जिले संबंधी आवश्यक एवं प्रतिनिधित्वकारी जानकारियों का समावेश है । यह नियमित रूप से अपडेट होती है । url :- -- http://www.khandwa.nic.in(2000)

7. जिला न्यायालय का कम्प्यूटरीकरण eCourt : यह प्रोजेक्ट सन 2010 में आरंभ किया गया । जिले की 2 कोर्ट का कम्प्यूटरीकरण किया जाकर साइट प्रीपरेशन और नेटवर्किग हो चुकी है । कम्प्यूटर हार्डवेयर भी प्राप्त हो चुका है । शीघ्र सॉफ्टवेयर का इंस्टालेशन कार्य किया जाकर कम्प्यूटरीकरण पूर्ण हो जाएगा ।

8. भारत आपदा संसाधन नेटवर्क India Disaster Resource Network(idrn): (http://idrn.gov.in) यह प्रोजेक्ट सन् 2004 में आरंभ हुआ है । इस परियोजना का उद्देश्य आपदाकाल में आवश्यक स्रोतो की जानकारी एकत्रित कर इन्टरनेट पर एक डाटाबेस के रूप में अद्यतन रखना है ताकि किसी भी प्रकार की राष्ट्रीय या क्षेत्रीय आपदा के समय स्रोतो का समुचित उपयोग आपदा के प्रभाव को न्यूनतम रखने में किया जा सके । जिले में उपलब्ध इसप्रकार के स्रोतों की जानकारी को उक्त साइट पर नियमित अद्यतन किया जाता रहा है ।

9. एकीकृत बालविकास परियोजना Integrated Child Development Services: महिला एवं बालविकास विभाग व्दारा संचालित एकीकृत बालविकास परियोजना के लिए इस साफ्टवेयर का विकास किया गया है । यह पिछली शताब्दी के अंतिम दशक से चल रहा है । यह एक मॉनिटरिंग साफ्टवेयर है ।

10. राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम National Social Assistance Programme(NSAP) (http://nsap.gov.in) राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के लिए NSAP 2009 में आरंभ किया गया । इसमें विभिन्न प्रकार की पेंशन योजनाओ जैसे वृद्धावस्था पेंशन योजना, विधवा पेशन योजना इत्यादि का समावेश किया गया है । लिगसी डाटा की एण्ट्री कर सामाजिक सहायता कार्यक्रम की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है । राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम 2009 में प्रारंभ हुआ, जिसके माध्यम से नि:शक्त, वृद्ध एवं विधवा पेंशन की सम्पूर्ण जानकारी वेबसाईट पर उपलब्ध कराई जाती है।

11. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना National Employment Guarantee act MIS.(NREGA MIS) (http://nrega.nic.in) इस एम आई एस को सन् 2006 से सफलतापूर्वक चलाया जा रहा है । . NREGA वर्शन 5.0 वर्तमान में प्रचलन में है । डाटा एण्ट्री विकासखण्ड स्तर पर एवं लाइन डिपार्टमेण्ट व्दारा की जा रही है । ऑफ लाइन व ऑन लाइन मोड में एण्ट्री की जा

रही है । ऑफ लाइन मेाड में एण्ट्री की दशा में नियमित अंतराल पर उसे वेबसाइट पर अपलोड भी किया जा रहा है ।

12. समेकित बिमारी निवारण कार्यकम Integrated Decease Surveillance Programme(IDSP) :- IDSP सन् 2008 में आरंभ हुआ . भारत शासन के स्वास्थ्य विभाग व्दारा सॉफ्टवेयर एन आइ सी के माध्यम से प्रदान किया जाकर सफलतापूर्वक संचालन किया जा रहा है ।

13. MP/MLALAD: यह प्रोजेक्ट सन् 1990 के बाद के दशक से चल रहा है । जनप्रतिनिधियों की स्थानीय विकास निधि के अंर्तगत किए जा रहे कार्यों की निगरानी के लिए इसका उपयोग किया जाता है ।

14. उपभोक्ता प्रतितोषण फोरम नेटवर्क Consumer Fora Network (CONFONET): उपभोक्ता प्रतितोषण न्यायालयों में विचाराधीन मामलों के प्रबंधन के लिए इस नेटवर्क एवं साफ्टवेयर का सन 2006 से उपयोग किया जा रहा है ।

15. Minor Irrigation Census: चतुर्थ लघु सिंचाई जनगणना 2008-09 में भू अभिलेख विभाग व्दारा की गई । इसका सर्वे डाटा एक साफ्टवेयर Minor irrigation Census में करते हुए भारत शासन को उपलब्ध कराया गया है।

16. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन National Rural Health Mission (http://nrhm.nic.in) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षत्रों में निवासरत गरीब महिलाओं एवं बच्चों को अच्छी स्वास्थ्य संबंधी सुविधायें उपलब्ध कराना एवं उनका उपयोग करना बताना है, जिससे उनके स्वास्थ्य स्तर में बढोतरी होकर वे निरोगी जीवन यापन कर सकें। स्वास्थ्य विभाग व्दारा इस मिशन के लिए उक्त साफ्टवेयर का 2010 से उपयोग किया रहा जाता है ।

17. स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना Swarnjayanti Gram Swarozgar Yojna sgsy (http://sgsy.gov.in) गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करनेवाले परिवारों के लोगों को इस योजना व्दारा लाभान्वित किया जाता है । यह 2010में आरंभ हुआ ।

18. प्रोजेक्ट ऐरो के अंतर्गत डाकघर कार्यालयों में इगवर्नेस :- डाकघरों को सन् 2008 से लीज्ड लाइन व्दारा एन आई से नेटवर्क से जोडा गया है और प्रोजेक्ट ऐरो एवं अन्य महत्वाकांक्षी कार्य इन्टरनेट के माध्यम से आरंभ हो गए है ।

19. वन संरक्षक कार्यालयों में नेटवर्क :- 2008 से ही वन संरक्षक कार्यालयों एवं निकटस्थ वन विभाग के कार्यालयों को नेटवर्क से जोडा गया है । इस विभाग की अपनी विडियो कांफ्रेस इकाई एवं अन्य इगर्वनेस के कार्य चल रहें है ।

20. परख PARAKH (11 Points) :- ग्यारह सूत्रीय कार्यक्रम के नाम से सन् 2001 से यह कार्यक्रम चल रहा है । मूलभूत सुविधाओं के अनुश्रवण में मध्यप्रदेश शासन इसका उपयोग जनपद स्तर से लेकर राज्य स्तर तक कर रहा है ।

21. समाधान एक दिन में ODG (One Day Governance) :- 15 अगस्त 2006 को आरंभ हुआ यह कार्यक्रम जिले की पांचो तहसीलों में सफलता पूर्वक चल रहा है । आय जाति के प्रमाणपत्रों, अनुज्ञप्ति नवीनीकरण एवं प्रमाणपत्र सत्यापन की सेवाऐ दी जा रही है ।

22. लोक वितरण प्रबंधन प्रणाली Food PDS : - सन् 2003 से यह कार्यकारी खाद्य विभाग व्दारा चलाया जा रहा है । खाद्य विभाग मासिक आंकडों का सम्प्रेषण विभाग की वेबसाईट पर करता है । एफ पी एस व्दारा मासिक आवंटन एवं उठाव की जानकारी का संधारण इस साफ्टवेयर में होता है ।

23. मुख्यमंत्री समाधान ऑनलाइन Samadhan Online :- जनशिकयत निवारण में तत्परता लाने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन ने 7 फरवरी 2006 से यह कार्यक्रम आरंभ किया । एन आइ सी मध्यप्रदेश व्दारा एक साफ्टवेयर का विकास किया जाकर उसपर 20 से 25 शिकायती आवेदनों का चुनाव गोपनीय और सावधानीपूर्वक किया जाकर रखा जाता है । संबंधित अधिकारियो को उनका प्रतिवेदन उसी दिन देना होता है और इन प्रतिवेदनो का अध्ययन मुख्यमंत्री महोदय व्दारा किया जाकर उसी दिन शिकायतकर्ता एवं अधिकारी के सम्मुख विडियो कांफ्रेंसिग के निराकरण किया जाता है ।

24. मुख्यमंत्री प्रबंधन सूचना प्रणाली CM MIS (http://mid.mp.nic.in/cmims) : - यह सन् 2006 में आरंभ हुई । विभिन्न विभागों के लिए यह प्रतिवेदन उपकरण (reporting tool) के रूप में उपयोग में लाया जाता है । विभाग विशेष अपनी जानकारिया इसमें भरता है और मान. मुख्यमंत्री कार्यालय इनका अध्ययन करता है ।

25. जन शिकायत निवारण Public Grievances on (www.mpsamadhan.org) :- जन साधारण इसमें अपनी समस्या / शिकायत दर्ज कर सकता है । इसका निवारण संबंधित विभाग व्दारा किया जाता है । जिला स्तर पर जिला कलेक्टर निगरानी एवं नियमन करता है ।

26. रूरलसाफ्ट Ruralsoft (http://www.mpsc.mp.nic.in/ruralsoft/):- यह भी सन् 2006 में आरंभ हुआ । यह Government-to Government (G2G) और Government-to Citizen (G2C) प्रकार का साफ्टवेयर है । .वेब आधारित यह साफ्टवेयर विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं जैसे इंदिरा आवास योजना (IAY), मुख्यमंत्री आवास योजना (MMAY),मध्यान्ह भोजन योजना (MDM), इत्यादि की निगरानी के लिए उपयोग होता है ।

27. मुख्यमंत्री घोषणा के लिए CM Jandarshan :- अपने जनदर्शन कार्यक्रम के अंतर्गत की गई घोषणाओं के क्रिान्वयन की निगरानी के लिए मुख्यमंत्री महोदय के लिए इस साफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है ।

28. वनवासी अधिकार पत्र सर्वे Forest Dwellers Survey (http://www.mpforest.org) वनाधिकार अधिनियम के अंतर्गत लाभान्वित वनवासियों को पटटा वितरण के लिए इस परियोजना का उपयोग किया गया । हेण्डहेल्ड जीपीएस इनेवल्ड डिवाइस व्दारा उचित वनवासी की जमीन का सर्वे किया जाकर उसका राज्य स्तर पर संधारण कर पट्टा वितरण कार्य किया गया । इसके अतिरिक्त अन्य कई गतिविधियाँ वनविभाग व्दारा इस पोर्टल से सम्पादित की जाती है । .

29. विभागीय निर्माणकार्यो की जानकारी Departmental Construction Works (http://lrdemo.nic.in) :- भू अभिलेख व्दारा 2009 से इस साइट का उपयोग किया जा रहा है । विभागीय निर्माण कार्य, नक्शों के डिजीटाइजेशन की जानकारी इत्यादि का संधारण प्रतिमाह भू अभिलेख, खण्डवा व्दारा किया जाता है ।

30. ई-स्कॉलरशिप (e-Scholarship) (http://www.scholarshipportal.mp.nic.in/Portal.aspx) :- ऑनलाइन वर्कफ्लो के रूप में इस सॉफ्टवेयर का उपयोग पेास्टमेट्रिक छात्रवृत्ति के लिए उपयोग किया जाता है । इस अनुप्रयोग में कई प्रक्रियाऐं जैसे आवेदनो कर प्राप्ति,प्रोसेसिंग और उनकी स्वीकृति इत्यादि का ऑटोमेशन किया गया है ।.

31. बैंक रिकवरी इंसेंटिव स्कीम BRISC (Bank Recovery Incentive Scheme) (http://www.dif.mp.gov.in/brisc/index.htm) :- मध्यप्रदेश लोकधन(शोध्य राशियों वसूली) अधिनियम 1987 के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के कर्जो की वसूली के लिए इस अनुप्रयोग का उपयोग किया जा रहा है । यह एक रोल आधारित अनुप्रयोग है ।

32. ई- खनिज E-khanij (http://mpsc.mp.nic.in/e_khanij/AppPrevious/HomePage.aspx) :-यह अनुप्रयोग 2009 में आरंभ किया गया । इसमे विभिन्न प्रकार की खनन जानकारियॉ जैसे खनिज उत्पादन, रॉयल्टी कलेक्शन, डेड रेण्ट कलेक्शन, कर वसूली और विभिन्न आवेदनो का समय पर निराकरण सुनिश्चित किया जाता है ।

33. विधानसभा प्रश्न उत्तर प्रबंधन प्रणाली VQRMS (Vidhan Sabha Question Reply Management System) (http://mpsc.mp.nic.in/vqrms) : - विधानसभा में पुछे जाने वाले प्रश्नो को इस अनुप्रयोग के व्दारा संबंधित विभाग को वेब पर दिए जाते हैं एवं संबंधित विभाग अपना उत्तर इसी वेब पर प्रविष्ठ करता है

34. समय सीमा पत्रक प्रबंधन सूचना प्रणाली TLMIS :- समय सीमा पत्रक प्रबंधन प्रणाली में कलेक्टर कार्यालय में आए हुए विभिन्न प्रकार के पत्रकों पर दी हुई समय सीमा में की गई कार्यवाही पर निगरानी ककी जाती है और साप्ताहिक बैठक में चर्चा की जाती है ।

35. शस्त्र लाइसेंस सूचना प्रणाली Arms : - यह प्रणाली भी सन 2000 के पूर्व से चली रही है । इस के द्वारा जिले मे वितरित शस्त्रो की जानकारी रखी जाती है ।

36. राजस्व वाद निगरानी प्रणाली Revenue cases Monitoring System: - जिला दण्डाधिकारी न्यायालय मे प्रचलित वादों की कॉज. लिस्ट निगरानी हेतु एनआईसी खण्डवा द्वारा MS-ACCESS में सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है।

37. जनशिकायतों की निगरानी/निराकरण प्रणाली Jan shikayat monitoring system :- कलेक्टर द्वारा जनसामान्य से जनसम्पर्क के दौरान प्राप्त शिकायतों की निगरानी/निराकरण हेतु यह सॉफ्टवेयर बनाया गया है, जिसमें कलेक्टर द्वारा जनशिकायतों को लिया जाता है एवं संबंधित विभाग को उन शिकायतों के निराकरण हेतु भेजा जाता है। कलेक्टर द्वारा शिकायतों की अद्यतन स्थिति साप्ताहिक रूप से देखी जाती है।

38. पंचायत युवा क्रिडा और खेल अभियान Panchayat Yuva Krida Aur Khel Abhiyan (PYKKA) (www.pykka.gov.in) :- देश के सभी गांव और ब्लॉक पंचायतों में खेलने के क्षेत्रों को चरणबद्ध तरीके के रखरखाव और विकास के लिए वर्ष 2008-09 में पंचायत युवा क्रिडा और खेल अभियान (PYKKA)की शुरूआत की गई। खेल प्रतिभाओं की पहचान के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण और राज्य द्वारा एक विशाल उन्हें अपनी योजनाओं के तहत राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में भाग लेने के लिए पोषण के लिए आधार, यह योजना ग्रामीण संगठित खेल में भाग लेने के युवाओं के लिए एक पर्याप्त अवसर प्रदान करता है.

39. इंदिरा आवास योजना Indira Awas Yojna (www.iay.nic.in) इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) मई 1985 में जवाहर रोजगार योजना की एक उप - योजना के रूप में शुरू किया गया था. यह 1 जनवरी 1996 के बाद से एक स्वतंत्र स्कीम के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है. इंदिरा आवास योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा (बीपीएल) अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों के लिए संबंधित के नीचे ग्रामीण लोगों की मदद करने में करना है

40. Annual Property Returns Management System (www.os.mp.nic.in/aprms) :- शासकीय कर्मचारियों एवं अधिकारियों द्वारा स्वयं घोषित उनकी चल-अचल सम्पत्ति की जानकारी इस वेबसाईट के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है।

41. Health – Mother and Child Tracking Program (www.mpsc.mp.nic.in/mcts):- माता शिशु ट्रेकिंग कार्यक्रम Mother and child Tracking Programme गभर्वती माता एवं गर्भउपरान्त शिशु

के स्वास्थ्य संबंधी आंकडों के संधारण के लिए इस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है । यह MMR/IMR/TFR को कम करने और स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं की डिलेवरी से संबंधित है ।

42. MP Loksewa Guarantee Adhiniyam (www.mid.mp.nic.in/mploksewa) मध्यप्रदेश शासन द्वारा लोक सेवाओं की प्रदान की गांरटी अधिनियम के माध्यम से लोक सेवाओं को प्रदान करने की गारंटी दी गई है। जनसामान्य को प्रदान की गई निश्चित समय में प्रदान की गई सेवाओं की जानकारी इस वेबसाईट के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है, जिसमें 9 विभागों की चिन्हित 26 सेवाओं की जानकारी दी जाती है।

43. PG Portal / CP GRAM – (www.pgportal.gov.in) – भारत सरकार की जनशिकायत निवारण प्रणाली। यह पोर्टल भारत सरकार द्वारा शिकायतों के निवारण के लिए नागरिकों को एक मंच उपलब्ध कराने के उद्देश्य से है. यदि आप देश में किसी भी सरकारी संगठन के खिलाफ कोई शिकायत दर्ज कराना चाहता है, तो आप अपनी शिकायत यहाँ दर्ज करायें। जो संबंधित मंत्रालय/ विभाग / राज्य सरकार को तत्काल निवारण के लिए के लिए भेजा जाता है।

44. PRI Profiler (http://164.100.72.23/priprofiler) :- पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की समस्त प्रकार की जानकारी के लिये वेब आधारित प्रणाली। अभी अभी चालू हुई है। इसके माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की जानकारी यथा पद एवं पदाधिकारी, भौगोलिक स्थिति, निर्मित संरचनाऐं, उपलब्ध स्वास्थ्य एवं शिक्षा सुविधा एवं अन्य जानकारियां उपलब्ध कराने के लिये यह वेबसाईट बनाई गई है।

45. कलेक्टर टूर डायरी के लिये वेब आधारित प्रणाली (https://vallabh.mp.nic.in/cdis/login.aspx):- कलेक्टर द्वारा किये गये भ्रणम से संबंधित जानकारी इस वेबसाईट के माध्यम से जिला स्तर पर दर्ज कराई जाती है तथा वह जानकारी आयुक्त एवं वरिष्ठ कार्यालयों को प्रेषित की जाती है।

46. Revised National Tuberculosis Program – (www.mpsc.mp.nic.in/rntcp) वेब आधारित प्रणाली जिसमें छय रोग से पीडित व्यक्ति के उपचार संबंधी सम्पूर्ण जानकारी तथा उसके पुनर्वास कार्यक्रम की सम्पूर्ण जानकारी प्रदान करते हुये संधारित की जाती है ताकि पीडित व्यक्तियों के सम्पूर्ण उपचार प्राप्त कर छय रोग से मुक्त हो सके।

47. स्पर्श अभियान (www.socialjustice.mp.gov.in) :- राज्य सरकार द्वारा नि:शक्तों की मदद के लिए चलेगा '' स्पर्श अभियान'' अभियान के जरिये नि:शक्तजनों का चिन्हांकन कर उनके उपचार/कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण/ स्वरोजगार, शिक्षण-प्रशिक्षण की व्यवस्था करना एवं पात्र नि:शक्त व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाना इस अभियान का प्रमुख उद्देश्य है।

48. सहाकारी समितियों के पंजीयन (http://www.mpsc.mp.nic.in/icdp) :- मध्यप्रदेश में सहाकारी समितियों के पंजीयन एवं उनको दिये जाने वाले विभिन्न प्रकार के ऋण एवं अन्य वित्तीय सहायताओं की जानकारी इस वेबसाईट के माध्यम से संधारित की जाती है।

49. Eight All India Education Survey (8th AISES) (http://aises.nic.in) :- आठवें AISES डेटा कार्यान्वयन की निगरानी और सर्व शिक्षा अभियान के प्रभाव का आकलन करने के लिए उपयोगी है, यूनिवर्सल एक्सेस, नामांकन, प्रतिधारण और गुणवत्ता के प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लिए शिक्षा योजना में सुधार प्रदान करेगा.

50. Crop Cuttings Experiments information System (http://mpsc.mp.nic.in/cropsagr/default.aspx) :- राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अंतर्गत फसलो की जानकारी सन्धारित करने के लिए इस वेब आधारित सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है।

51. Ex-Servicemen Personnel Registration and Schemes Monitoring System (ExPReSS) (http://mpsc.mp.nic.in/express):- यह एक वेब आधारित सॉफ्टवेयर भूतपूर्व सैनिक (ईएसएम), उनकी विधवाओं और युद्ध विधवाओं का एक केंद्रीकृत डेटाबेस बनाने के लिए है। इसके अलावा यह विभिन्न केन्द्रीय / राज्य सरकारी योजनाओं जैसे (क) रोजगार पंजीकरण (ख) पुनः रोजगार के लिए प्रशिक्षण (ग) वित्तीय सहायता (घ) शैक्षिक छात्रवृत्ति आदि की जानकारी रखने हेतु भी है।

52. डेस्कटॉप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा SWAN नेटवार्क के माध्यम से ब्लॉक स्तर तक की गई है । डेस्कटॉप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा जिले मे स्थित विभाग अपने अधिनस्त ब्लॉक स्तर के विभागो से जानकरी लेने हेतु वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते है ।

53. मध्य प्रदेश स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क (MPSWAN) राज्य में ई - शासन पहल के लिए एक सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग के एक माध्यम प्रदान करता है। यह परियोजना राज्य सरकार के विभागों, सार्वजनिक उद्यमों और ई - शासन परियोजनाओं के उपयोग के लिए हैं ।

54. State Finance Monitoring System (MP Treasury) :- जिले में सरकार के सभी वित्तीय लेनदेन के लिए Treasury नोडल कार्यालय का कार्य कर रही है । जो कि भुगतान और सरकार से वित्तीय प्राप्तियों का प्रबंधन करता है। आरेखण और संवितरण अधिकारी जो पैसे के लेन-देन लिए अधिकृत है Treasury मे अपने दावे पेश करते है।